JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत के विकास के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन (मेक इन इंडिण्या विषेष संदर्भ)

डॉ. मनोज मिश्रा
प्राचार्य
विवेकानंद महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

डॉ. आषीष दुबे
सहायक प्राध्यापक
विवेकानंद महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

सारांष

आर्थिक विकास का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है समय परिवर्तन के साथ–साथ आर्थिक विकास का प्रारूप भी लगातार बदलता रहा हैं। मानवीय सभ्यता के प्रारंभिक चरण में जहाँ कृषि मानवीय जीवन एवं सभ्यता का आधार था जो मूलरूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में विकास हुआ । एतिहासिक साहित्यों के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रारंभिक मानवीय सभ्यता के उदय से लेकर औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक चारण से पूर्व तक कृषि की मानवीय जीवन एवं सभ्यता का आधार हैं।

प्रस्तावनाः– औद्योगिक क्रांति के साथ ही हमारी सभ्यता का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ जिसमें औद्योगिक विकास को विषेष स्थान दिया गया । यही औद्योगिक विकास शहरीकृत अर्थव्यवस्था आधार बना। भरतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर विदेषी दस्ता, विकेन्द्रीय कृत शासन व्यवस्था, तथा उपनिवेषवाद का नाकारात्मक प्रभाव पड़ा । स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार परंपरागत कृषि प्रणाली ही रही जिसके प्रभाव से भारतीय समाज में आर्थिक असमानता का अत्यंत व्यापक स्तर पर व्याप्त थी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक नियोजन कार्यक्रमों के क्रियांवयन के साथ ही भारत में आधुनिक औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हुई । प्रारंभिक आद्योगिक विकास को तीन भागों में विभाजित किया गया, कुटीर, लघु एंव वृद्ध उद्योग । इन उद्योगों के संचालन क्षेत्रों को भी तीन भागों में विभाजित किया गया निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र । नियोजन काल के प्रारंभिक चरण में योजनाबद्ध औद्योगिक विकास का अभाव रहा जिसके कारण निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग अधिकांषतः असफल रहे । इन उद्योगो की सफलता का प्रमुख कारण वित्तीय प्रबंधन की असफलता रही जिसका अत्यंत नकारात्क प्रभाव स्थानीय लघु उद्योगों पर पड़ा । देष की अर्थव्यवस्था में भी लगातार गिरावट दर्ज की गयी। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगो की असफलता का प्रमुख कारण विदेषी ऋणों की अधिकता, अकुषल प्रबंधन तथा लालफिताषाही रही ।

1991 में अपनाई गयी निजीकरण, वैष्वीकरण एवं उदारीकरण की नीति देष में औद्योगिक विकास के प्रक्रिया का द्वितीय चरण रहा जिसके अंतर्गत औद्योगिक विकास की प्रक्रिया को सरल बनाना तथा औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्रों तथा विदेषी कंपनियों को भारत के औद्योगिक विकास में प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ाना था । इस नीति का प्रारंभिक चरण देष के औद्योगिक विकास के लिए लाभदायक रहा तथा प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिक विकास की दर 6 प्रतिषत वृद्धि दर को प्राप्त करने में सफल रहा जो धीरे धीरे बढ़ कर 9 प्रतिषत वृद्धि दर से भी अधिक पहुच गया इस प्रकार भारतीय

अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल हो गयी । निजी क्षेत्रों की आद्योगिक विकास के क्षेत्र में बढ़ती हुई भागीदारी वित्तीय क्षेत्रों में पृथक चुनौती उत्पन्न कर रही थी विदेष निवेषों का बढ़ता आकार स्थानीय उद्योगों के लिए लगातार चुनौतियाँ उत्पन्न कर रही थी विदेषी निवेषों का बढ़ता आकार स्थानीय उद्योगों के लिए लगातार चुनौतियाँ उत्पन्न कर रहा था। बाजार में भी स्थानीय उद्योगों की सीमित प्रतियोगी क्षमता बड़े विदेषी औद्योगिक उत्पादों का सामना करने में सफल नहीं थे । धीरे–धीरे उक्त तथ्यों का नकारात्मक प्रभाव देष के आर्थिक विकास पर पड़ा । वर्ष 2010 तक स्थानीय औद्योगिक क्षेत्रों में विदेषी पूँजी विनियोगों का नकारात्मक प्रभाव दिखायी देने लगा और देष के औद्योगिक विकास गति भी धीमी पड़ने लगी । अतः स्थानीय उद्योगों को गति देने के लिए नयी औद्योगिक नीति की आवष्यकता महसूस की जाने लगी । स्थानीय औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मेक इन इण्डिया कार्यक्रम की घोषणा सितम्बर 2014 को तथा स्टार्टअप इण्डिया कार्यक्रम की घोषाण 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी द्वारा की गयी।

उद्देष्यः–

1. मेक इन इण्डिया एवं स्टार्टअप योजनाओं को समझना ।
2. योजनाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
3. योजनाओं का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बाजार पर प्रभाव का अध्ययन करना ।

शोध प्रविधिः– यह शोध कार्य पूर्णतः द्वितीयक समंको पर आधारित हैं । विभिन्न संचार माध्यमों पत्रिकाओं एंव समाचार पत्रों में मेक इन इण्डिया तथा स्टार्टअप इण्डिया से संबंधित साहित्यों का अध्ययन किया गया है तथा इन साहित्यों के आधार पर इन योजनाओं की सरल व्याख्या प्रस्तुत किया गया हैं।

मेक इन इण्डिया योजना भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत देष में निवेष एवं नवाचार को बढावा देने बौद्धिक सम्पदा की रक्षा करने तथा देष में विष्व स्तरीय विनिर्माण आधार मूल ढाँचा को निर्माण करने के लिए आवष्यक कदम उठाना है । इस कदम ने भारत में विनिर्माण उद्यमियों के नयी दिषा प्रदान किया तथा देष में औद्योगिकरण की प्रक्रिया एवं औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया को सरल बनाने में औद्योगिकरण को नयी दिषा प्राप्त हुई ।

विष्लेषण एवं तर्कः– मेक इन इण्डिया योजना का प्रमुख उद्देष्य सरकार द्वारा वैष्विक बड़ी–बड़ी औद्योगिक संस्थाओं को आकर्षित करने के लिए उचित नियमन करना तथा उन्हें आवष्यक सुविधाएँ प्रदान करना है जिससे भारत में आयात बिल कम हो सके तथा देष में रोजगार का सृजन हो । भारत में मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण औद्योगिकरण बढ़ावा देने तथा वैष्विक व्यापार व्यवस्था को सुदृण बनाने के लिए 25 सितम्बर 2014 को मेक इन इण्डिया योजना का आरंभ देष के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया जिसके अंतर्गत भारत को महत्वपूर्ण निवेष एवं निर्माण संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैष्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करना है । मेक इन इण्डिया कार्यक्रम मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र के विकास प्रक्रिया से संबंधित है जिसका मुख्य उद्देष्य देष में उद्यमषीलता की बढ़ावा देना निवेष के अनुकूल वैष्विक औद्योगिक विकास के ढाँचे का निर्माण करना आधुनिक एवं कुषल आधार मूल संरचना का निर्माण करना, प्रत्यक्ष विदेषी निवेष के लिए नये क्षेत्रों को खोलना तथा सरकार एवं उद्योग के स्थापित क्रियान्वयन के बीच उचित समन्वय कर देष में वृहत औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र का निर्माण करना हैं। मेक इन इण्डिया योजना के माध्यम से आयात बिलों में नियंत्रण स्थापति कर सकारात्मक व्यापार संतुलन का निर्माण करना भी इस योजना के उद्देष्यों में शामिल हैं।

मेक इन इण्डिया या भरत में बनाओं योजना को वैष्विक स्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई हैं। अभियान के शुरू होने के समय से इसकी वेबसाइट पर बारह हजार से अधिक सवाल इनवेस्टर इण्डिया के निवेषक सुविधा प्रकोष्ठ द्वारा प्राप्त किया गया हैं। जापान, चीन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया जैसे अनेक देषों के उद्यमियों के द्वारा देष में

विभिन्न निर्माण क्षेत्रों के आधारभूत ढ़ाचों को स्थापित करने के लिए देष में निवेष करने के लिए अपनी सहमति दिया हैं मेक इन इण्डिया के प्रारंभिक चरण में पच्चीस विभिन्न उत्पाद क्षेत्रों का चयन किया गया हैं जिन में निम्न शामिल है ऑरों अवयव, आटोमोबाईल, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन निर्माण, रक्षा उत्पादन विद्युत मषीनरी, इलेक्ट्रनिक सिस्टम डिजाइन और निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण आई.टी. एवं बीपी एम, मीडिया एवं मनोरंजन, खदान, तेल एवं गैस फामस्यिटिकल, बन्दगाह एंव नौवाहन, रेल्वे, सड़क एंव राजमार्ग नवीकरणीय, उर्जा, अंतरिक्ष वस्त्र एवं परिधान, थर्मल पावर, पर्यटन एवं आथित्य तथा मानवीय कल्याण क्षेत्र शामिल हैं।

मेक इन इण्डिया योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं। देष में व्यवसाय को सरल बनाने के लिए विभिन्न व्यावसायिक नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाया है तथा उनके वस्तुओं के विनिर्माण के लिए लाईसेन्स की जरूरतों को समाप्त किया हैं। सरकार के उद्देष्य देष में संस्थाओं के साथ ही आवष्यक सुविधाओं के विकास द्वारा व्यवसायिक गतिविधियों के लिए सुदृढ आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना हैं। सरकार व्यापरिक संस्थाओं को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक गलियारों तथा स्मार्ट सिटि की स्थापना का लक्ष्य रखा हैं। राष्ट्रीय कौषल विकास मिषन के द्वारा देष में कुषल मानव संसाधन के विकास का प्रयोजन किया गया हैं। पेटेंट तथा ट्रेडमार्क पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं आकर्षक बना कर देष में नवीन प्रयोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारत में बनाओ योजना के उद्देष्यों में नए औद्योगिकरण को आकर्षित करना तथा देष में आधुनिक सुदृढ़ औद्योगिकरण हेतु आधार तैयार करना विनिर्माण क्षेत्रों में 12–14 प्रतिषत वार्षिक वृद्धि दर निष्चित करना देष के सकल घरेलु उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी वर्ष 2022 तक 16 प्रतिषत से बढ़कर 25 प्रतिषत करना, वर्ष 2022 तक 100 मिलयन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना तथा निर्यात आधारित विकास को बढ़ावा देना हैं । इस योजना के लागू होने के पश्चात् प्रत्यक्ष विदेषी निवेष में आकर्षक वृद्धि हुई है। वर्ष 2014–15 में भारत में प्रत्यक्ष विदेषी विनियोग 45.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो वर्ष 2021–22 में बढ़कर 83.6 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया हैं। हाल के वर्षों में आर्थिक सुधारों के द्वारा 100 अरब अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य वर्ष 2022–23 में रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में खिलौनों का आयात 70प्रतिषत घटकर (877.8 करोड़ रूपए) हो गया हैं। भारत में खिलौनों के निर्यात में वर्ष 2022 में वर्ष 2013 तुलना में 636 प्रतिषत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020–21 में भारत में बनाओं योजना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोडक्षन लिंक्ड इंसेटिव (PLI) योजना प्रारंभ की गयी हैं।

मेक इन इण्डिया कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सितम्बर 2021 में राष्ट्रीय एक खिड़की प्रणाली (NSWS) का सितम्बर 2021 में शुभारंभ किया गया जिससे अन्तराष्ट्रीय निवेष प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके यह एक डिजिटल प्लेटफार्म हैं जिसके माध्यम से अंतराष्ट्रीय निवेष एवं व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के निवेष संबंधित क्रियांनवयनों में समन्वय स्थापित किया गया है जिससे देष में व्यापार तथा निवेष की प्रक्रिया सरल हो । सरकार द्वारा देष में विनिर्माण क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री गतिषक्ति कार्यक्रम का संचालन किया गया है। यह कार्यक्रम विनिर्माण क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों के मध्य व्यावसायिक संचालन में समन्वय स्थापित करेगा तथा इकाईयों की व्यावसायिक क्षमता में वृद्धि करेगा। देष के हथकरघा, हस्तषिल्प वस्त्र, कृषि तथा कृषि एवं प्रसंस्करण उद्योगो को प्रोत्साहित करने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना का संचालन किया जा रहा हैं जो देष के स्थानीय उत्पादकों को वैष्विक व्यापार मंच उपलब्ध करा रहा है जिससे देष के सामाजिक तथा आर्थिक विकास को एक नयी दिषा प्राप्त हुए है तथा देष के स्थानीय करीगरों तथा उत्पादकों के आय में भी वृद्धि हुई हैं।

निम्न गुणवत्ता और खतरनाक खिलौनों के आयात को नियंत्रित करने तथा देष में स्थानीय विनिर्माण खिलौनों के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने मूल सीमा शुल्क विदेषी खिलौनों पर 20 प्रतिषत से बढ़ाकर 60 प्रतिषत कर दिया है साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण ओदष का कार्यान्वयन आयतित खिलौनों का अनिवार्य नमूना परीक्षण घरेलु खिलौनों निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं खिलौना उद्योग समूहों का सामूहीकरण आदि अनेक रणनीतिक नियोजन किया गया है जिसका प्रभाव देष के खिलौना उद्योगो के विकास पर दिखलाई दे रहा हैं। औद्योगिक विकास में अर्द्धचालक उत्पादकों की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिक होती है ये उत्पादक विनिर्माण क्षेत्र में बड़े उद्योगों को स्थापित करने में मुख्य आधार का कार्य करने है। ये उत्पादक विनिर्माण के क्षेत्र में बड़े उद्योगो को स्थापित में मुख्य आधार का कार्य करते है। ये उत्पादक वृद्ध उद्योगो की विभिन्न आवष्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है सरकार द्वारा देष में अर्द्धचालक परिस्थिति तंत्र के निर्माण के लिए 10 बिलयन अमेरीकी डॉलर की प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया गया हैं।

मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेषी निवेष को प्रोतसाहित करने के लिए विभिन्न विनिर्माण क्षेत्रों में विदेषी निवेष प्रतिषत में वृद्धि किया गया हैं रक्षा क्षेत्र में विदेषी पूँजी निवेष नीति को उदार बनाया गया है इस क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26 प्रतिषत से 49 प्रतिषत तक बढ़ाया गया है एवं अत्याधुनिकी प्रौद्योगिकी के लिए रक्षा क्षेत्र में 100 प्रतिषत एफडीआई की अनुमति दी गयी है उक्त नीतियों के कारण ही हमारा देष रक्षा क्षेत्र में प्रमुख निर्यातक के रूप में वैष्विक बाजार में स्थान बनाने में सफल रहा है। अंतरीक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेषी निवेष को 100 प्रतिषत तक करने की स्वीकृति प्रदान किया गया है जिसके कारण भारत अंतरीक्ष प्रौद्योगिक क्षेत्र में लगातार उपलब्धियाँ अर्जित करने जा रहा हैं। विष्व के अनेक अंतरीक्ष से संबंधित प्रौद्योगिक संस्थान भारतीय अंतरीक्ष संस्थान इसरों की उपलब्धियों से आकर्षित होकर प्रौद्योगिक यहयोग स्थापित कर रहे है । रेल्वे के आधारभूत ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए इस क्षेत्र में भी 100 प्रतिषत से प्रत्यक्ष विदेषी निवेष की अनुमति दी गयी है वर्ष 2014 के पश्चात् इस भारतीय रेल व्यवस्था में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त किया गया है। रेल्वे व्यवस्था में परियोजनाओं के निर्माण संचालन एवं स्वचालित मार्ग रख रखाव आदि क्षेत्रों में शत् प्रतिषत विदेषी निवेष की अनुमति दी गयी है इन नियोजनों के परिणाम स्वरूप देष के रेल क्षेत्र की आधारभूत व्यवस्थाओं में अत्यंत प्रषंसनीय विस्तार हुआ है जिसमें माल ढुलाई, यात्री परिवहन आदि क्षेत्रों में हुए अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त किया गया है जिसमें वन्दे मातरम् एक्सप्रेस अत्यंत महत्वपूर्ण है जो 180 कि.मी. की गति से यात्री परिवहन कार्य संपादित करती है। माल ढुलाई के व्ययों को कम करने के लिए देष में एल्मुनियम के ढुलाई यानों का तथा मालगाड़ी के लिए पूरे देष में पृथक परीवहन नेटवर्क या रेल्वे पथ का निर्माण किया जा रहा है तथा माल गाड़ी परिवहन के लिए पूरे देष में पृथक परिवहन नेटवर्क या रेल्वे पथ बनाने की योजना भी संचालित किया जा रहा है। अनुमान है कि देष में स्वनिर्मित बुलेट वर्ष 2025 से पूर्व किया जा सकेगा तथा वर्ष 2030 से पूर्व देष में हाइड्रोजन से चलने वाली इन्जनों का भी निर्माण किया जाएगा जो देष में परिवहन क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। बीमा तथा चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में भी मेक इन इण्डिया में निवेषकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देष्य से निवेषक सुविधा प्रकोष्ट का गठन किया गया है जिसे इन्वेस्ट इण्डिया नाम दिया गया है इस प्रकोष्ठ में निवेषकों को सुविधा प्रदान करने के लिए विषेषज्ञों की नियुक्ति की गयी है ।

मेक इन इण्डिया कार्यक्रम भारत में विनिर्माण उद्योग के आधारभूत संरचना के निर्माण क्षेत्र में एक सफल कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के कारण भारत में औद्योगिक निर्माण उद्योगों के स्थापना एवं विकास के लिए सकारात्मक पर्यावरण का निर्माण हुआ तथा देष में महत्वपूर्ण रोजगार का सृजन हुआ । इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप देष के निर्यात में वृद्धि हुई तथा महत्वपूर्ण विदेषी मुद्रा एवं निवेष की प्राप्ति हुई । स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक चरण में जहाँ विदेषी ऋणों पर आधारित विकास कार्यक्रम के प्रभावों से देष का विकास अत्याधिक प्रभावित था वही आज विदेषी पूँजी

एक आधुनिक तकनिकी का संयोजन विनिर्माण के क्षेत्र में देष के उत्पादों को नयी ऊँचाई प्रदान कर रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जहाँ हमारा देष क्षेत्र छोटे औद्योगिक उत्पादों के लिए विदेषों पर निर्भर था वही आज आत्याधुनिक वायुयान, पानी जहाज, पनडुब्बी, हथियार, टैंक, रॉकेट जैसे अनेक महत्वपूर्ण उत्पादों का निर्माण मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में हो रहा है और इन उत्पादों के निर्यात के माध्यम से देष विदेषी मुद्रा अर्जित कर रहा है । मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के समक्ष देष में अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी है। भारतीय एफडीआई का बड़ा भाग न तो विदेषी है और न ही प्रत्यक्ष निवेष यह निवेष मुख्यतः मारीषस स्थित शैल कंपनियों से आता है जिसके बारे में संदेह है कि वे भारतीय काले धन है जिनका निवेष मारीषस स्थित शेल कंपनियों के माध्यम से भारत में किया जा रहा है। भारतीय श्रमिक सामान्यतः अकुषल है इन श्रमिकों के लिए उचित प्रषिक्षण की व्यवस्था का अभाव है जिसका नकारात्मक प्रभाव भारतीय औद्योगिक उत्पादकता पर पड़ता है । देष में आधुनिक लघु औद्योगिक उत्पादन पर भी उपलब्धता सीमित है जिसका प्रभाव वृहद् विनिर्माण क्षेत्रों पर पड़ता है । भारत में औद्योगिक विद्युत आपूर्ति भी संतोषजनक नही है विद्युत आपूर्ति के लिए आधुनिक सौर ऊर्जा परमाणुक ऊर्जा संयंत्र एवं अन्य आधुनिक ऊर्जा आपूर्ति संयंत्रों का अभाव है। भारतीय षिक्षा प्रणाल में व्यापक सुधार की आवष्यकता है जिसमें देष के आधुनिक औद्योगिक नियोजन के संबंध में शैक्षणिक सामग्रियों का अभाव है जिसका प्रभाव भारत के औद्योगिक विकास पर पड़ता है। भारतीय प्रषासनिक व्यवस्था में व्याप्त लाल फिताषाही का भी नकारात्मक प्रभाव देष के औद्योगिक विकास पर पड़ता है । देष में परिवहन व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मानी जा सकती है देष में परिवहन व्यवस्था के सुधार के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिसका सकारात्मक प्रभाव देष के औद्योगिक विकास पर पड़ रहा हैं।

उपसंहारः– इस योजना के प्रारंभ हुए लगभग 8 वर्ष पूर्ण हो गये इस अवधि में देष के विनिर्माण एवं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । वर्ष 2019–20 से लेकर वर्ष 2021–22 के अवधि में महामारी कोविड–19 के नकारात्मक प्रभाव देष के सभी विकास क्षेत्रों पर पड़ा तथा इस अवधि का प्रभाव भी मेक इन इण्डिया कार्यक्रम की गति पर पड़ा है। कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित 12 प्रतिषत से 14 प्रतिषत औद्योगिक विकास दर को प्राप्त कर पाना अत्यंत चुनौतिपूर्ण लक्ष्य है । मेक इन इण्डिया कार्यक्रम ने भारत में औद्योगिक विनिर्माण के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियाँ प्राप्त किया है किन्तु अनेक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान है । भारतीय प्रषासनिक मषीनरी को अधिक कुषल एवं स्वस्थ्य बनाने की आवष्यकता है। भारत में नियामक निर्माण प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं दीर्घकालक है जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष विदेषी निवेष पर पड़ता है इसलिए विदेषी निवेषों को प्रोत्साहित करने के लिए संतुलित पर्यावरण पारदर्षी नियमन एवं न्यायिक प्रक्रिया में सरलता एवं स्थिरता लाने की आवष्यकता है। भारत की दलगत राजनीति भी भारत के औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधा है। वर्तमान स्थिति में सत्ता रूढ़ दल एवं विपक्षी दलों के मध्य उचित समन्वय का अभाव है सामान्यतः हमारे देष में विरोध की राजनीति ही होती है जिसका दुष्प्रभाव देष आर्थिक समाजिक औद्योगिक व्यापारिक विकास पर पड़ता है । हमारे देष की राजनीतिक व्यवस्था में भी द्विदलीय पद्धति लागू किये जाने की आवष्यकता है। क्षेत्रीय दलों एवं उन दलों पर नियंत्रण आवष्यक है जो देष विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है इस प्रकार की गतिविधियों पर भी नियंत्रण के लिए त्वरित प्रषासनिक एवं न्यायिक प्रक्रिया आवष्यक है । देष मे श्रम को कुषल बनाने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है लेकिन ये प्रयास संतोषजनक नहीं है श्रम प्रषिक्षण कार्यक्रमों के विस्तार की आवष्यकता है जिके माध्यम से देष में कुषल श्रम संसाधनों का निर्माण हो सके कुषल श्रम संसाधनों का विस्तार देष में औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र के विकास का आधार होगा । अंत मे यह स्पष्ट है कि मेक इन इण्डिया कार्यक्रम का योगदान भारत में औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र के विकास एवं विस्तार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा तथा इस कार्यक्रम ने अपने 8 वर्षों की कार्यावधि में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था को विष्व की

पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने मे मेक इन इण्डिया कार्यक्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा इस योजना का कुषल क्रियान्वयन ही वर्ष 2030 तक भारत को विष्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में सफल रहेगी।

संदर्भ

1. मेक इन इण्डिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नया प्रमाण ।
2. ग्रेट माइन्ड्स ऑन इण्डिया, सलिल गेवली ।
3. Make in India official web site.
4. Make in India: A key of sustainable growth - Dr. Vishal Bisnoi
5. Make in India: A Roadmap to sustainable growth - M. Kamal